ला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य के कौन कौन से जिले पिछले साल वर्षा की असफलता के कारण दुर्भिक्ष से ग्रस्त हुए ;

(ख) कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा और उसके परिणामस्वरूप जान तथा मवेशियों की कितनी हानि हुई;

(ग) गुजरात सरकार ने दुर्भिक्ष ग्रस्त लोगों के विकास के लिये कितना अनुदान मांगा है तथा वास्तव में कितना अनुदान दिया गया; और

(घ) लोगों को दुर्भिक्ष के प्रभाव से बचाने के लिये उठाये गये ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनिर्निर्माण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) गुजरात सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बनासकंठा, सावर-कंठा, पंचमहल, कच्छ, सुरेन्द्र नगर, मेहसाणा, अहमदाबाद खेड़ा, भड़ोच, बलसड़, राजकोट, जामनगर अमरेली, भावनगर तथा जूनागढ़ जिलों में वर्ष 1980–81 के दौरान वर्षा न होने के कारण कृषि कार्यों में विभिन्न मात्रा में मन्दी की स्थिति पैदा हो गई थी।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार इससे 23 लाख मानव तथा 5 लाख पशु प्रभावित हुए थे । मानव जीवन की कोई क्षति नहीं हुई ।

(ग) तथा (घ). केन्द्रीय दल, जिसने 19 से 20 मई, 1980 के बीच राज्य का दौरा किया था, की रिपोर्ट तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने राज्य सरकार की 4298 लाख रुपये की मांग की तुलना में 1980–81 की मानसून पूर्व अवधि के दौरान सूखे से प्रभावित जनसंख्या को राहत प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सहायता के तौर पर 612 लाख रुपये के अधिकतम व्यय की मंजूरी दी ।

अहमदाबाद, अमरेली, बनासकंठा, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मेहसाणा, पंचमहल, राजकोट तथा सुरेन्द्र नगर जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जारी है । इस कार्यक्रम के तहत वन रोपण, जल संसाधनों का विकास तथा प्रबन्ध, नुदा तथा नमी संरक्षण, पशुधन फार्मिंग का विकास तथा चरागाह व चारा विकास सम्बन्धी कार्य आता है ।

बनासकंठा, मेहसाणा तथा कच्छ जिलों में एक मरुस्थल विकास कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के तहत आने वाले मुख्य कार्य वन-रोपण, चरागाह विकास, बालू के टीलों का स्थिरीकरण, भूमिगत जल विकास तथा उपयोग, जल उपयोग के उपाय, कृषि विकास, बागवानी तथा पशु पालन आदि हैं ।

Erosion by Ganga in Murshidabad

3057. SHRI ZAINAL ABEDIN: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware about the erosion by the Ganga in Murshidabad district of West Bengal;

(b) whether Government of West Bengal demanded Rs. 293 crore to implement anti-erosion scheme; and

(c) if so, action taken by the Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI) : (a) and (b). Yes Sir.

(c) All work required for the safety of the various components of the Farakka Barrage complex have been undertaken by the project Authorities. As the State Governments are responsible for formulating and implementing flood control work out of their respective plan funds, protective measures in other reaches are to be undertaken by the West Bengal Government. The Central Government took up the

question of helping the State Government in sharing with the State Government the cost of anti-erosion by other beneficiaries, like the Roads and the Railways in the areas where such installations exist. The State Government has been requested to furnish a recast scheme showing the minimum cost of such works and other cost-benefit ratio, the same is still awaited from the State Government.

Rural Development Programme in Country

3058. SHRI ARJUN SETHI : Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the rural development programme in the country is legging behind the expectation of the Experts and the Government also;

(b) if so, what are the names of the projects which have been undertaken under the programme;

(c) what are the details regarding the assistance given by the Union Government to various States for the programme; and

(d) the active steps being taken by Government to boost the programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM) : (a) to (c). The major centrally sponsored rural development programmes are integrated rural development programme, the drought prone areas programme and the national rural employment programme. A statement showing the assistance provided by the Centre, funds utilised and physical achievements under each programme in various states during 1980-81 is laid on the Table of the House. [*Placed in library. See No.* LT-2776/81]. The achievements under the aforesaid programmes differ from State to State depending upon the efforts put in by them.

(d) the performance under these programmes is being monitored and reviewed regularly and administrative, organisational and other inputs are provided in adequate measure to achieve the targets Discussions between representatives of the Central Ministry and State Govts. are held periodically in the State-level coordination committees. Central teams also visit districts and blocks to study the implementation of these programmes. Field officers are provided systematic training for improving performance and monitoring arrangements are being strengthened.

ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए बिहार को दी गई राशि

3059. **श्री कुंवर राम** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए दी गई मद-वार राशि कितनी है ;

(ख) इस धनराशि में से नवादा तथा नालन्दा जिलों में कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) वहां पर निर्मित अथवा निर्माणाधीन पक्की सड़कों के नाम क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ऐसी कोई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों जिन में बिहार भी शामिल है, को विशेषरूप से निधियों का आवंटन किया जाता हो। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है राज्य क्षेत्र में है तथा इसके लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की